बदलाव के केन्द्र में ढांचागत विकास

प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की बड़ी राशि ढांचागत विकास पर खर्च होगी। इससे प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। तरक्की को और रफ्तार देने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर चार और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समानांतर दो औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किये जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निकट भी औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के बाद सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2017-18 से ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर वर्ष थीम आधारित बजट पेश किया है। वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था, वित्त वर्ष 2018-19 में ढांचागत विकास और औद्योगिक विकास पर फोकस किया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए समर्पित रहा। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 का बजट युवाशक्ति, कौशल विकास, रोजगार और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर 'स्वावलंबन से सशक्तीकरण' के लक्ष्य को समर्पित था। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 'अंत्योदय से आत्मनिर्भरता' का बजट था और इस बार 2023-24 का बजट प्रदेश के 'त्वरित सर्वसमावेशी विकास' को समर्पित है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

भारी व मध्यम उद्योगों को तरजीह

अवस्थापना सुविधाओं और औद्योगिक गलियारों का होगा विकास

प्रदेश के बजट में भारी और मध्यम उद्योगों के लिए 20586 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही सभी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दो लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से डिफेंस कॉरिडोर के झांसी और चित्रकूट नोड तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे औद्योगिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी।

20586
करोड़ रुपये की व्यवस्था भारी एवं मध्यम उद्यम मद में

भारी और मध्यम उद्योग के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 9826.95 करोड़ रुपये पूंजीगत मद यानी नई संपत्तियों के सृजन पर खर्च होंगे। इसमें दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, उपभोक्ता उद्योगों व अन्य उद्योगों के मद में बजट की व्यवस्था की गई है।

नए औद्योगिक विकास व निवेश के लिए अवसर खोलने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और यातायात का दबाव कम करने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसी तरह चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्टेट डाटा सेंटर को विकसित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उप्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, उप्र. स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड और स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की शासकीय देयताओं के भुगतान के लिए 878.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्पिनिंग कंपनियों के बकाये के लिए 287.95 करोड़ रु.

उप्र. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की रायबरेली, मऊनाथ भंजन और बाराबंकी इकाइयों पर बकाया ऋण और अंशपूंजी मद में अनुदान के लिए 287.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ व हरदोई सीमा पर टेक्सटाइल पार्क

लखनऊ और हरदोई सीमा पर कृषि विभाग की चिह्नित 1000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

तेज होगा रेलवे ओवर ब्रिज और अंडरपास का निर्माण

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट से लखनऊ समेत प्रदेश भर की तमाम रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रेलवे अंडरपास (आरयूबी) और रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इससे लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। आरयूबी व आरओबी के निर्माण, मरम्मत, चालू कार्य पूरा करने समेत अन्य कार्यों के लिए 1624 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में नेशनल हाईवे के रास्ते पर पड़ने वाली क्रॉसिंग के आरओबी व आरयूबी के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी तरह 354 करोड़ रुपये से आरओबी व आरयूबी बनाए जाएंगे। वर्तमान में बनाए जा रहे पुलों को 630 करोड़ रुपये से पूरा कराया जाएगा। मौजूदा पुलों की मरम्मत के लिए 90 करोड़ रुपये, वर्तमान आरओबी और आरयूबी के रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपये और पुलों को अत्याधुनिक बनाने की कंसल्टेंसी के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1624 करोड़ रुपये का प्रावधान, जाम से मिलेगी मुक्ति